posed to cover the remaining schools during the VIIIth Plan. The progress of implementation of Operation Blackboard is given in Annexures IV. (See Appendix CLXI, Annexure Nos. 40, 41, 42 and 43]

Recommendations regarding Agro-Economic Research

*238. SHRI RAM NARESH YADAV: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) what are the recommendations of the Review Committee for improving the performance of Agro-Economic Research Centres and their units; and

(b) what steps Government have taken to implement these recommendations?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI BALRAM JAKHAR): (a) The main recommendations of the Review Committee pertaining to improving the performance of Agro-Economic Research Centres and Units at the Institute included (i) the AER Centres to be put on a permanent footing, (ii) the AER Centres be made an integral part of their respective Universities retaining their separate identity, (iii) Strengthening of AER Centres/Units as also AER Branch of the Directorate of Economics & Statistics, (iv) strengthening of analytical capability of the Centres by providing mini-computers, (v) undertaking studies covering fundamental problems of Indian agriculture and rural economic change including common studies of All-India relevance and inter-regional analysis and (vi) need for improvement of the timelines in the completion of studies and preparation of reports.

(b) The recommendations of the Review Committee were examined by Empowered Committee set up by the Ministry in March, 1984 and were by and large accepted by the Government. As a follow-up of these recommendations, the AER Centres have been declared permanent institutions by the Ministry on 21-5-90. The recommendations relating to the integration of A.E.R. Centres/Units with the respective Universities/Institutes is being processed and that relating to the strengthening of the staff of the Centres/Units would be taken up after the finalisation of the Eighth Five Year Plan. In order to improve the analytical facilities for research, the Centres have been provided mini-computers as also photo copier machines recently. Periodic reviews have been arranged with the Centres to monitor the progress of the research studies assigned to them.

New Steel Plants in Goa

*239. SHRI JOHN F. FERNANDES: Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) whether Government have issued any license to any firm for the setting up new steel plant in Goa;

(b) if so, what is the name of the firm and by when this plant is likely to start production; and

(c) what would be its estimated capacity?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL (SHRI SONTOSH MOHAN DEV): (a) and (b) Government issued a letter of intent in 1985 to M/s. M.G. Poy Raiturcar (later changed to M/s. Marmagoa Steel Ltd.) for setting up a composite mini steel plant at Curtorim, Salcete, Goa. As per information filed by the applicant, commercial production is expected to commence by the end of December, 1991.

(c) As per information filed by the applicant, the proposed annual capacity of the unit is as follows:

Item of Manufacture	Annual capacity
1, Steel ingots/billets	1,50,000 Tonnes
2, Rolled products like rounds and flats	1,30,000 Tonnes

उत्तर प्रदेश में निरक्षरता

*240. **मौलाना अबदुल्ला खान आजमी :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में निरक्षरता कितने प्रतिशत है ;

(ख) इस समय उत्तर प्रदेश में निरक्षरता कितने प्रतिशत है ; और

(ग) सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में निरक्षरता दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) वर्ष 1991 की जनगणना के अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार, पूरे देश और उत्तर प्रदेश में, 7 वर्ष और उससे अधिक की आयु वाली जनसंख्या के संबंध में निरक्षरता की दर क्रमश: 47.89 प्रतिशत और 58.29 प्रतिशत थी ।

(ग) प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण जिसमें अनौपचारिक शिक्षा और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, शामिल हैं, जिसका उद्देश्य वर्ष 1995 तक 15–35 वर्ष की आयु वर्ग के 8 करोड़ प्रौढ़ निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना है, उत्तर प्रदेश राज्य सहित देश में निरक्षरता उन्मूलन के व्यापक कार्यक्रम का अभिन्न अंग है । इस उद्देश्य की प्राप्त के लिए राज्य में जो विशेष उपाय किए गए हैं। किए जा रहे हैं, वे निम्न प्रकार हैं :

(i) साक्षरता के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने हेतु गांधीवादी और सर्वोदय के कार्यकर्ताओं की टीमों द्वारा 43 जिलों में 1755 जत्थे आयोजित किए गए । जिनमें 35000 गांवों को शामिल करते हुए इस प्रक्रिया में लगभग 3.00 लाख स्वयंसेवकों का पता लगाया गया । इसी तरह, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक स्वैच्छिक एजेंसी भारत ज्ञान विज्ञान समिति ने राज्य भर में जत्थे आयोजित किए ।

(ii) फतेहपुर, मेरठ और सोनभद्र (चार ब्लाक) जिलों में पूर्ण साक्षरता अभियान शुरू किये गये । कुछ और जिलों को भी ऐसे अभियानों में शीघ्र ही शामिल किए जाने की संभावना है ।

(iii) नेहरू युवा केन्द्रों द्वारा राज्य के 25 जिलों में 4700 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चलाए जा रहे हैं ।

(iv) राज्य में 12726 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों और 104 जन शिक्षण निलयमों को चलाने के लिए अभी तक 136 स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता प्रदान की गई है ।

(v) नव साक्षरों को उत्तर साक्षरता तथा सतत शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 2108 जन शिक्षण निलयमों (ज० शि० नि०) की संस्वीकृति प्रदान कर दी गई है जिनमें से 1608 जन शिक्षण निलयमों के चालू होने की सूचना मिली है ।

(vi) क्षेत्र विशेष, समयबद्ध और लागत प्रभावी बनाने के लिए परंपरागत, केन्द्र आधारित कायक्रम को पुनर्गठित किया गया है ।

(vii) सभी 895 ब्लाकों में 65,388 प्राथमिक स्कूलों को आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है ।